वर्ष 11 अंक 03 जुलाई-सितम्बर 2025

जलागम दर्पण

जलागम प्रबन्ध निदेशालय द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका

जलागम विभाग में मनाया गया उत्तराखण्ड का लोकपर्व हरेला

उत्तराखण्ड के लोकपर्व हरेला के अवसर पर जलागम प्रबंध निदेशालय में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जलागम मंत्री श्री सतपाल महाराज थे। निदेशालय परिसर में श्री सतपाल महाराज ने रुद्राक्ष व अन्य अतिथियों, अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा आंवला, चंपा, चीकू, हरड़, गुलमोहर, आम, अंजीर, बेल आदि के पौधे लगाए गए।

इस अवसर पर जलागम मंत्री श्री सतपाल महाराज ने बच्चों में भी पौधे लगाने के संस्कार पैदा करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण एक वैश्विक विषय है और इसके प्रति सभी की जिम्मेदारियां हैं। उन्होंने कहा कि जलागम एक विभाग ही नहीं बल्कि भविष्य है। हर्बल पौधे लगाए जाएं तथा कार्बन क्रेडिट के माध्यम से ग्राम पंचायत की आय को बढ़ाने के प्रयास किए जाएं। ऐसे पौधे लगाए जाएं, जिन्हें जानवर नुकसान न पहुंचा सकें। राज्य गठन की परिकल्पना को साकार करते हुए उत्तराखंड के उत्पादों को बढ़ावा दिया जाना है। उन्होंने नौले, धारे आदि जलस्रोतों के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान देने को कहा।

जलागम मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वृक्षों के महत्व को जन-जन तक पहुंचाने के लिए एक पेड़ मां के नाम मुहिम चलाई है, इसमें सभी की सहभागिता आवश्यक है।

स्थानीय विधायक श्रीमती सविता कपूर ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण किया जाना सभी के लिए आवश्यक है। इसके विषय में सभी को गंभीरता से सोचना होगा और अपना योगदान देना होगा। मुख्य परियोजना निदेशक श्री दिलीप जावलकर ने कहा कि जलागम विभाग की तरफ से अगले साल से हरेला पर्व और व्यापक स्तर पर आयोजित किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस संबंध में आयोजन किए जाएंगे। परियोजना निदेशक श्री हिमांशु खुराना ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण संबंधी कार्यों को लेकर अन्य विभागों से भी समन्वय किया जा रहा है। सामूहिक योगदान से बेहतर परिणाम सामने आएंगे।

इस अवसर पर संयुक्त निदेशक डा. ए.के. डिमरी, डा. एस.के. सिंह, मुख्य वित्त अधिकारी श्री दीपक भट्ट, उप परियोजना निदेशक श्री एन.एस. बरफाल, डा. मीनाक्षी जोशी तथा विभागीय कर्मचारी उपस्थित थे।

निदेशालय के साथ ही विभिन्न प्रभागों तथा यूनिटों में भी हरेला पर्व पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान ग्रामीण समुदाय के साथ मिलकर पौधरोपण कार्यक्रम किए गए तथा लोगों को पौधों को बचाने के प्रति भी प्रेरित किया गया।

ग्रीन लैंडस्केप मैनेजमेंट प्लान : संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र व सशक्त आजीविका की दिशा में सफल पहल

ऋषिकेश में 26 से 28 अगस्त 2025 तक तीन दिवसीय अंतरराज्यीय कार्यशाला "ग्रीन लैंडस्केप मैनेजमेंट प्लान: संतुलित व सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र से सशक्त समुदाय–आजीविका" सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस कार्यशाला ने विभिन्न राज्यों और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों को साझा मंच प्रदान किया, जहाँ जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण, कृषि और आजीविका के संतुलन पर ठोस रणनीतियों पर चर्चा हुई।

कार्यशाला का शुभारंभ जलागम सचिव श्री दिलीप जावलकर (IAS) एवं परियोजना निदेशक श्री हिमांशु खुराना (IAS) की उपस्थिति में हुआ। अपने उद्बोधन में श्री जावलकर ने कहा कि ग्रीन-एजी परियोजना कृषि और पर्यावरण के बीच एक सशक्त सेतु का कार्य कर रही है। जलवायु परिवर्तन, भूमि क्षरण और जैव विविधता ह्रास जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए लैंडस्केप स्तर पर सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि यदि यह पहल सफल होती है तो यह भारत सहित विश्व के लिए एक मॉडल बनेगी। उन्होंने जैविक इनपुट प्रशिक्षण, इको क्लब स्थापना और महिला कृषक समूहों के कौशल विकास जैसी गतिविधियों का उल्लेख करते हुए जलागम मंत्री श्री सतपाल महाराज के मार्गदर्शन में हो रहे कार्यों की सराहना की।

कार्यशाला में ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी (GEF), फ़ूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन (FAO) के रीजनल एशिया पसिफ़िक मुख्यालय, बैंकॉक से समीर कार्की (जेफ तकनीकी अधिकारी), शायला वर्टज़ व एक्सेल बूले (वरिष्ठ वानिकी अधिकारी), कोंडा रेड्डी (असिस्टेंट एफ ए ओ रिप्रेजेन्टेटिव), मनोज मिश्रा (राष्ट्रीय तकनीकी समन्वयक), डॉ ए.के. डिमरी, संयुक्त निदेशक, एन.एस. बरफाल तथा डॉ. डी.एस. रावत, उप निदेशक जलागम विभाग का विशेष योगदान रहा|

प्रतिभागियों ने राजाजी–कार्बेट लैंडस्केप में लैंटाना उन्मूलन, चैनलिंक फेंसिंग, जियोमेंब्रेन टैंक, ड्राई स्टोन चेकडैम और परती भूमि विकास जैसे हस्तक्षेपों का अवलोकन कर समुदायों से संवाद किया। विशेषज्ञ प्रस्तुतियों, समूह चर्चाओं और अनुभव साझा करने के माध्यम से ग्रीन लैंडस्केप मैनेजमेंट प्लान पर गहन विचार-विमर्श हुआ। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी द्वारा वित्तपोषित ग्रीन-एजी परियोजना भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा FAO के सहयोग से संचालित है, जिसका उत्तराखंड में क्रियान्वयन जलागम विभाग द्वारा किया जा रहा है।

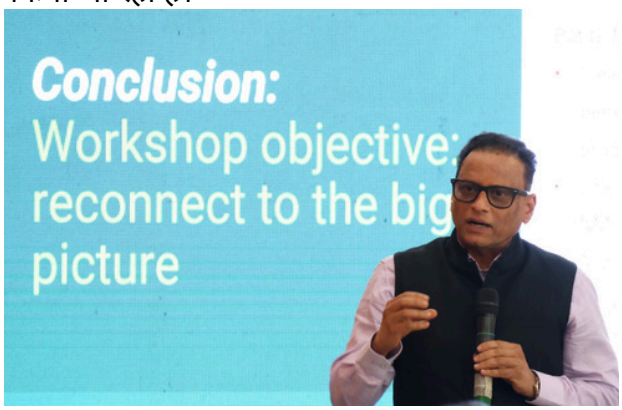

मीडिया कवरेज

हरेला हमारी सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा : महाराज

- नौलों-धारों के संरक्षण लिए जलागम ने बनाया भगीरथ एप
- मंत्री ने किया जलागम दर्पण पत्रिका का भी किया लोकार्पण

देहरादून (एसएनबी)। हमारी सरकार उत्तराखण्ड के प्राकृतिक संसाधनों और यहां की हरियाली के संरक्षण के लिए अत्यंत गंभीर है। इसके लिए हर स्तर प्रयास किए जा रहे हैं। जलागम विभाग द्वारा भी केन्द्र पोषित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जलागम घटक 2.0 और विश्व बैंक वित्त पोषित उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना के माध्यम से हरियाली और पानी को संरक्षित करने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं।

पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बुधवार को इंदिरानगर स्थित जलागम निदेशालय परिसर में लोक पर्व हरेला पर पौधरोपण करने के पश्चात आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अपने संबोधन में कही। उन्होंने प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हरेला पर्व उत्तराखण्ड की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण लोकपर्व है। यह पर्व प्रकृति और हरियाली के प्रति हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाता है। हर वर्ष श्रावण मास में मनाया जाने वाला यह लोकपर्व नई फसलों की शुरुआत का प्रतीक है। यह सामाजिक सद्भाव के साथ-साथ हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

जलागम मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जलागम विभाग के अंतर्गत स्प्रिंग एण्ड रिवर रिजुवेनेशन एथरिटी (सारा) का गठन भी किया गया है। इसके अंतर्गत नौलों और धारों के संरक्षण में सभी प्रदेशवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भगीरथ एप बनाया गया है। इसके माध्यम से वह अब तक पाँच हजार से अधिक जलस्रोत चिह्नित किए जा चुके हैं।

इस अवसर पर विधायक सविता कपूर, जलागम सचिव दिलीप जावलकर, परियोजना निदेशक डा.हिमांशु खुराना, डा. एसके डिमरी, डा.एसके सिंह, नवीन सिंह बरफाल, डा.मीनाक्षी जोशी, दीपचंद सहित जलागम के अनेक कर्मचारी एवं अधिकारियों उपस्थित थे।

नौलों-धारों के संरक्षण के लिए तैयार होगा जीआईएस प्लेटफॉर्म : महाराज

अमर उजाला ब्यूरो

पंचायतों को 29 विषय हस्तांतरण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के निर्देश

देहरादून। पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि पंचायत स्तर पर प्राकृतिक जलस्रोत नौलों-धारों के संरक्षण के लिए जीआईएस प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर समिति गठित की जाएगी। उन्होंने पंचायतों को 29 विषय हस्तांतरण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए।

शुक्रवार को पंचायतीराज निदेशालय में पंचायत व जलागम विभाग की समीक्षा बैठक में विभागीय मंत्री महाराज ने कहा- स्प्रिंग एंड रिवर रेजुवेनेशन अथारिटी (सारा) के माध्यम से प्राकृतिक जलस्रोतों के संरक्षण में स्थानीय लोगों की सहभागिता के लिए जीआईएस प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है।

उन्होंने पर्यावरण में कार्बन डाईऑक्साइड एवं जहरीली गैसों के उत्सर्जन के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए खाली पड़ी निजी व सरकारी भूमि पर पेड़ लगाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। केंद्र पोषित योजना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की कार्य योजना में प्रगति के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। इसके अलावा 73वें संविधान संशोधन की 11वीं अनुसूची के अनुसार 29 विषयों की निधि, कार्यों व कार्मिक त्रिस्तरीय पंचायत को हस्तांतरित करने के लिए शीघ्र प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए।

महाराज ने कहा, वित्तीय 2025-26 में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत 179.40 करोड़ की वार्षिक योजना स्वीकृत है। इसके तहत 25 करोड़ की पहली किस्त जारी की गई।

पंचायतीराज विभाग में सहायक पंचायत विकास अधिकारी के खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। बैठक में सचिव जलागम दिलीप जावलकर, पंचायती राज निदेशक निधि यादव, जलागम की परियोजना निदेशक कहकशा नसीन, अपर सचिव पंचायती राज श्याम सिंह, संयुक्त सचिव ध्रुव मोहन राणा, त्रिपाठी, अपर निदेशक मनोज तिवारी, रविनाथ रमन त्रिपाठी, डॉ. अनुज कुमार डिमरी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

किसानों को सशक्त बनाना परियोजना का उद्देश्य: खुराना

जलागम विभाग में धान की खेती विषय पर कार्यशाला शुरू

अमर उजाला ब्यूरो

देहरादून। उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना (यूसीआरआरएफपी) के परियोजना निदेशक हिमांशु खुराना ने कहा कि परियोजना के तहत ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने का एक मॉडल तैयार किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि क्षमता विकास के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाना परियोजना का एक मुख्य उद्देश्य है, ताकि परियोजना समाप्ति के बाद भी किसान अपनी आजीविका बेहतर तरीके से चला सके। यह बात परियोजना निदेशक खुराना ने जलवायु अनुकूल वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों पर आधारित धान की खेती विषय पर दो-दिवसीय कार्यशाला में कही। कार्यशाला का आयोजन जलागम विभाग के सहयोग से किया गया। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक से आए वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. अंजनी कुमार ने कहा कि देश में कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का 18 प्रतिशत हिस्सा खेती का है और खेती में भी 18 प्रतिशत उत्सर्जन सिर्फ धान की फसल से होता है। ऐसे में धान की सीधी बुआई (डीएसआर) व कम पानी से अधिक धान की उपज जैसी तकनीकों पर अधिक जोर दिया जा रहा है। डॉ. अंजनी कुमार ने कहा कि मीथेन का उत्सर्जन पिछले सौ वर्षों में दो गुना से ज्यादा हो चुका है।

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर भी मंथन

डॉ. अंजनी।

कार्यशाला में ग्रीन हाउस गैसों के अधिक उत्सर्जन की वजह से हो रहे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर भी मंथन किया गया। कार्यशाला में अधिक बारिश, तापमान में बदलाव, सूखा व बाढ़ के बदलाव की स्थिति तथा उसके नियंत्रण में प्रभावी धान की वैरायटी पर भी चर्चा हुई। इस दौरान विशेषज्ञों ने धान की बुआई से लेकर उत्पादन तक इस्तेमाल होने वाली विभिन्न तकनीकों के विषय में भी विस्तार से बताया। कार्यशाला में क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस तथा धान की सीधी बुआई के विषय में भी जानकारी दी गई। ज्ञात हो कि उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना परियोजना के माध्यम से जलागम विभाग उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में इन तरीकों का प्रयोग करेगा।

जीवन और पर्यावरण के बीच संतुलन जरूरी: जावलकर

ऋषिकेश, संवाददाता। मुनिकीरेती जलागम कार्यालय में ग्रीन लैंडस्केप मैनेजमेंट प्लान विषय पर अंतरराज्यीय कार्यशाला बुधवार को संपन्न हुई।

सचिव जलागम दिलीप जावलकर ने कार्यशाला में जलागम मंत्री सतपाल महाराज की निगरानी में जलागम के कार्यों पर प्रकाश डाला। कहा कि राज्यों में ग्रीन एजी परियोजना कृषि और पर्यावरण के बीच सेतु का काम कर रही है। मौजूदा वक्त में जैव विविधता घट रही है। भूमि क्षरण बढ़ रहा है। ऐसे वक्त में वास्तविक कार्य लैंडस्केप स्तर पर ही संभव है। जीवन और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करने की जरूरत है। कार्यशाला में उत्तराखंड, मिजोरम, उड़ीसा और मध्यप्रदेश के प्रतिनिधि शामिल रहे। इस मौके पर समीर कार्की, शायला वर्टज, एक्सेल बूले, कोंडा रेड्डी, मनोज मिश्रा आदि मौजूद रहे।

किसानों से सामंजस्य बनाकर काम करेगा जलागम विभाग

- मुख्य परियोजना निदेशक ने किसानों तक जानकारी पहुंचाने पर दिया जोर

जलागम विभाग में चल रही दो दिवसीय कार्यशाला का समापन।

देहरादून (एसएनबी)। जलवायु परिवर्तन पर कृषि की भूमिका व ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने को लेकर जलागम विभाग में चल रही दो दिवसीय कार्यशाला का समापन हो गया। उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना (यूसीआरआरएफपी) के अंतर्गत आयोजित इस कार्यशाला में धान की खेती में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा की गई।

शनिवार को समापन सत्र में राज्य स्तरीय जलागम परिषद के उपाध्यक्ष लंकर कोरंगा ने जलागम विभाग और किसानों के बीच सामंजस्य से काम करने की बात कही। उन्होंने कहा कि बेहतर सामंजस्य से परियोजना का वास्तविक लाभ किसानों तक पहुंचेगा। जलागम सचिव व मुख्य परियोजना निदेशक दिलीप जावलकर ने कहा कि ग्रीन हाउस गैस एक विकराल समस्या के रूप में हमारे सामने है। इसे देखते हुए कृषि के तरीकों में भी बदलाव आवश्यक हो गया है।

स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवेनेशन अथॉरिटी (सारा) की परियोजना निदेशक कहकशां नसीम ने कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण बेहद लाभकारी होते हैं। अब यहां से लिए ज्ञान को फील्ड में बेहतर तरीके से क्रियान्वित कराना महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे पहले कंसोर्सिया पार्टनर केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक से आए वरिष्ठ वैज्ञानिक डा.अंजनी कुमार ने धान की पारंपरिक खेती के अन्य वैकल्पिक तरीकों पर विस्तार से जानकारी दी।

कार्यशाला में जलागम निदेशालय के अधिकारी, फील्ड अधिकारी व कार्मिकों के साथ ही विभिन्न जिलों के धान उत्पादक कृषक उपस्थित थे।

ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन घटाने को लेकर हुआ मंथन

देहरादून : जलवायु परिवर्तन में कृषि की भूमिका व ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन घटाने को लेकर शुक्रवार को जलागम में दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना के अंतर्गत कार्यशाला में यूसीआरआरएफपी के परियोजना निदेशक हिमांशु खुराना ने कहा कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को घटाने को एक माडल तैयार किया जाएगा। तराई क्षेत्रों के बाद इसे प्रदेश के अन्य हिस्सों में अपनाया जा सकेगा। (जासं)

ग्रीन हाउस गैसों का 18 फीसद उत्सर्जन खेती से

- ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करने पर जलागम विभाग में मंथन

देहरादून। वरिष्ठ संवाददाता। जलवायु परिवर्तन पर कृषि की भूमिका व ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने को लेकर शुक्रवार को जलागम विभाग में वैज्ञानिक, नीति निर्माताओं तथा किसानों ने मंथन किया। उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना (यूसीआरआरएफपी) के अंतर्गत आयोजित आयोजित कार्यशाला में धान की खेती में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा की गई।

कार्यक्रम का शुभारम्भ करते हुए परियोजना निदेशक यूसीआरआरएफपी हिमांशु खुराना ने कहा कि परियोजना के तहत ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने का मॉडल तैयार किया जाएगा। इसे बाद में प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी अपनाया जा सकेगा। कंसोर्सिया पार्टनर केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक से आए वैज्ञानिक डा. अंजनी कुमार ने कहा कि देश में कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का 18 प्रतिशत हिस्सा खेती का है। खेती में भी 18 प्रतिशत उत्सर्जन सिर्फ धान की फसल से होता है। ऐसे में धान की सीधी बुआई व कम पानी से अधिक उपज पर सरकार अधिक जोर दे रही है।

ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने पर कार्यशाला में हुआ मंथन

जलवायु परिवर्तन पर कृषि की भूमिका व ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने को लेकर 29 तथा 30 अगस्त को जलागम विभाग में वैज्ञानिक, नीति निर्माताओं तथा किसानों ने मंथन किया। जलागम निदेशालय में आयोजित दो-दिवसीय कार्यशाला का विषय जलवायु अनुकूल वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों पर आधारित धान की खेती रखा गया था। उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना (यूसीआरआरएफपी) के अंतर्गत आयोजित इस कार्यशाला में धान की खेती में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा की गई। परियोजना के माध्यम से जलागम विभाग उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में इन तरीकों का प्रयोग करेगा।

कार्यशाला में राज्य स्तरीय जलागम परिषद के उपाध्यक्ष श्री शंकर कोरंगा ने जलागम विभाग और किसानों के बीच सामंजस्य से काम करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि बेहतर सामंजस्य से परियोजना का वास्तविक लाभ किसानों तक पहुंचेगा। जलागम सचिव व मुख्य परियोजना निदेशक श्री दिलीप जावलकर ने कहा कि

ग्रीन हाउस गैस एक विकराल समस्या के रूप में हमारे सामने है। इसे देखते हुए कृषि के तरीकों में भी बदलाव आवश्यक हो गया है।

इस अवसर पर परियोजना निदेशक, यूसीआरआरएफपी श्री हिमांशु खुराना ने कहा कि परियोजना के तहत ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने का एक मॉडल तैयार किया जाएगा, जिसे बाद में प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी अपनाया जा सकेगा। स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवनेशन अथॉरिटी (सारा) की परियोजना निदेशक श्रीमती कहकशां नसीम ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण बेहद लाभकारी होते हैं।

कंसोर्सिया पार्टनर केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक से आए वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. अंजनी कुमार ने धान की पारम्परिक खेती के अन्य वैकल्पिक तरीकों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस तथा धान की सीधी बुआई (डीएसआर) के विषय में भी जानकारी दी गई। कार्यशाला में जलागम निदेशालय के अधिकारीगण, फील्ड से आए अधिकारी व कार्मिकों के साथ ही विभिन्न जिलों के धान उत्पादक कृषक उपस्थित रहे।

जलागम दर्पण- वर्ष 11, अंक 03, जुलाई-सितम्बर 2025

संरक्षक- दिलीप जावलकर, मुख्य परियोजना निदेशक

संपादक मंडल

हिमांशु खुराना, परियोजना निदेशक
कहकशां नसीम, परियोजना निदेशक
डा. ए.के. डिमरी, संयुक्त निदेशक
डा. डी.एस. रावत, उप परियोजना निदेशक
डा. मीनाक्षी जोशी, उप परियोजना निदेशक
मनीष ओली, नॉलेज मैनेजमेंट एक्सपर्ट

हमारा पता

जलागम दर्पण
जलागम प्रबन्ध निदेशालय
इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कालोनी
देहरादून, उत्तराखण्ड